



DNA

डेली न्यूज ऐक्टिविस्ट

RNI NO.: UPHIN/2007/41982 संस्करण : लखनऊ

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

website : www.dnahindi.com

डाक पंजीयन : एसएसपी/एल.डब्ल्यू./एन.पी.-358/2016-18

8 डेली न्यूज ऐक्टिविस्ट

लखनऊ, शुक्रवार, 12 जुलाई 2019

दृष्टिकोण

www.dailynewsactivist.com

जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण के खतरे

यह सर्वविदित तथ्य है कि विश्व जनसंख्या यानी वर्तमान में मनुष्यों की कुल संख्या एक सदी के भीतर बहुत अधिक बढ़ गई है। अप्रैल 2019 तक विश्व की जनसंख्या 7.7 बिलियन लोगों की आंकी गई थी। जबकि दुनिया की आबादी को एक बिलियन तक पहुंचाने में मानव इतिहास के दो लाख वर्ष लग गए थे, लेकिन पिछले दो सौ वर्षों के भीतर यह सात बिलियन तक पहुंच गई। साल 1315 से 1317 तक के महाअकाल के अंत और साल 1350 में ब्लैक डेथ के बाद से यह 370 मिलियन के आसपास थी। उसके बाद वैश्विक जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रही और साल 1955 से साल 1975 के बीच जनसंख्या वृद्धि प्रतिवर्ष 1.8 प्रतिशत की दर से तथा साल 1965 से साल 1970 के बीच उच्चतम वृद्धि 2.1 प्रतिशत तक बढ़ गई। फिर साल 2010 से साल 2015 के बीच यह वृद्धि दर घटकर 1.2 प्रतिशत पर आ गई। अनुमान जताया गया है कि आगे मौजूदा 21वीं सदी के अंत तक इसमें और गिरावट आएगी। हालांकि संपूर्ण वैश्विक जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है और साल 2050 में इसके लगभग दस बिलियन यानी एक हजार करोड़ और साल

2100 में 11 बिलियन यानी एक हजार 100 करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान है। मालूम हो कि 1980 के दशक के अंत में कुल वार्षिक जन्म लगभग 139 मिलियन था और इसके साल 2011 तक 135 मिलियन के स्तर पर स्थिर रहने की अनिवार्य रूप से उम्मीद थी, क्योंकि इसी बीच मृत्यु दर प्रति वर्ष 56 मिलियन थी और साल 2040 तक प्रति वर्ष बढ़कर इसके 80 मिलियन होने की उम्मीद है। विश्व की जनसंख्या की औसत आयु साल 2018 में 30.4 वर्ष होने का अनुमान लगाया गया था। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, जबकि अगले 30 वर्षों के भीतर औसत मृत्यु दर 42.8 प्रतिशत होगी और पर्यावरणीय खतरे के कारण इसमें और वृद्धि हो सकती है। इस संदर्भ में विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या मुद्दों की तात्कालिकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। यह 11 जुलाई 1987 को पहली बार मनाया गया और साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग कार्डिनल द्वारा पांच बिलियन ब्याज दर का दिन लागू किया गया था, जिसमें परिवार नियोजन के मानव अधिकार को बनाए रखने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत नौ

अभिमत



● डॉ. भरत राज सिंह

brsingh1ko@gmail.com

मानकों मसलन गैर भेदभाव, परिवार नियोजन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग, परिवार नियोजन की वस्तुएं और सेवाएं सभी के लिए सुलभ, स्वीकार्य, अच्छी गुणवत्ता, सूचित निर्णय लेना, एकांत और गोपनीयता, भागीदारी और जवाबदेही के रूप में प्रस्तुत कर विश्व जनसंख्या नियंत्रण की पहल की

गई। परिवार नियोजन के इन मानकों को साल 1987 से शुरू करने से भी हम अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप विश्व की जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सके, जो निश्चित ही एक विषम स्थिति दर्शाता है। दरअसल, हमने अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण न करके अपने आराम के लिए उत्पादन में वृद्धि और प्रशासनिक मुद्दों की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से बढ़ावा देकर पृथ्वी के संसाधनों का शोषण किया है- हाइड्रोकार्बन ईंधन, वनों की कटाई, खेती की भूमि बनाने में वृद्धि, रहने के लिए घरों की आवश्यकता, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया। अब यही हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए चिंता का कारण है, अन्यथा पूरी वैश्विक आबादी, प्रजातियां और अन्य आजीविकाएं इनके समाप्त होने तक के गंभीर परिणामों का सामना कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांतियों के दृष्टिकोण के साथ आज कारखानों में रसायनों का उपयोग खतरनाक मात्रा में बढ़ गया है। इसके साथ ही औद्योगिक या आर्थिक उद्देश्यों के कारण वनों की कटाई और प्राकृतिक गैस,

तेल और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक जलने से वायुमंडलीय कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा 315 पीपीएमवी यानी मात्रा प्रति मिलियन से बढ़कर लगभग 363 पीपीएमवी हो गई है। ये कुछ प्राथमिक कारण हैं जिनके कारण वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। भविष्य में विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन से होनेवाली विनाशकारी घटनाओं जैसे तूफान, भारी बारिश, बाढ़, भूकंप और भारी भूस्खलन के साथ पहाड़ी क्षेत्र में भारी बर्फबारी, हिमस्खलन आदि का सामना करने के साथ वैश्विक जनमानस भारी नुकसान से प्रभावित होंगे। इन प्रभावों से मानवता भी उच्च जोखिम में होगी, विकास बिखर जाएगा और बचाव का प्रयास उच्च प्राथमिकता प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें पृथ्वी और जीवन को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कुछ मुद्दों पर तेजी से काम करना होगा। इसकी प्राथमिकता में जनसंख्या नियंत्रण, अधिकाधिक वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, एलईडी बल्ब का उपयोग, वाहनों में पेट्रोलियम ईंधन का उपयोग न कर अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना आदि शामिल है।